nylon yarn under control so that yarn could be made available to industry at reasonable prices and closure of large scale textile factories be avoided; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) Punjab Government had approached Union Government in the past for bringing pricing and distribution of nylon and viscose yarn and viscose filament yarn under control in view of the short supply and high prices of these yarns at that time in Amritsar market. Punjab Government is reported to have approached the Central Government again recently on this subject suggesting control of pricing and distribution in view of the difficulties being faced by the Warp Knitting Industry in Amritsar.

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण की वापसी अदायगी

6455. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अब तक कितनी राशि के ऋण प्राप्त किए गये हैं; और

(ख) प्रत्येक अवसर पर उक्त ऋण प्राप्त करने के क्या आधार हैं और वापस अदायगी की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना और बातों के साथ साथ मुद्रा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और उसके संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाने, सदस्यों को पर्याप्त संरक्षणों के अन्तर्गत कोष के सामान्य साधनों को अस्थायी तौर पर उपलब्ध कराने उनमें आत्मविश्वास जागृत करने तथा सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान शेष के विसंतुलन की अवधि और मात्रा को कम करने के लिए की गई थी ।

भारत ने 1947-48 और 1975-76 के बीच भुगतान शेष की आवश्यकताओं और निर्यात में हुई कमी को पूरा करने के लिए प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा (कम्पेन्सेटरी फाइनेंसिंग फेसिलिटी) तेल सुविधा और सोना प्रारक्षित भंडार तथा ऋणों की किस्तों (क्रेडिट ट्रांशे) जसी 186.45 करोड़ एस० डी० आर० (1283.05 करोड़ रुपए) के मूल्य कोष की सुविधाओं का उपयोगय किया। उपर्युक्त सभी निकासियों की पूरी तरह वापसी आदायगी कर दी गई है और अब इस संबंध में कोष की कोई देनदारी बकाया नही है।

Credit facilities to small entrepreneurs

6456. SHRI NITYANANDA MISRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the nationalised banks are not following the directions issued by the Reserve Bank of India for issue of credit facilities to small entrepreneurs whose cases are recommended by District Industrial centres especially in Orissa; and

(b) if so, the steps Government propose to take in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) No, Sir. Reserve Bank of India have reported that they have not received any complaint in this regard from small entrepreneurs in Orissa.

(b) Does not arise.